VEDANGA
INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES

बजट और सर्वेक्षण 2023

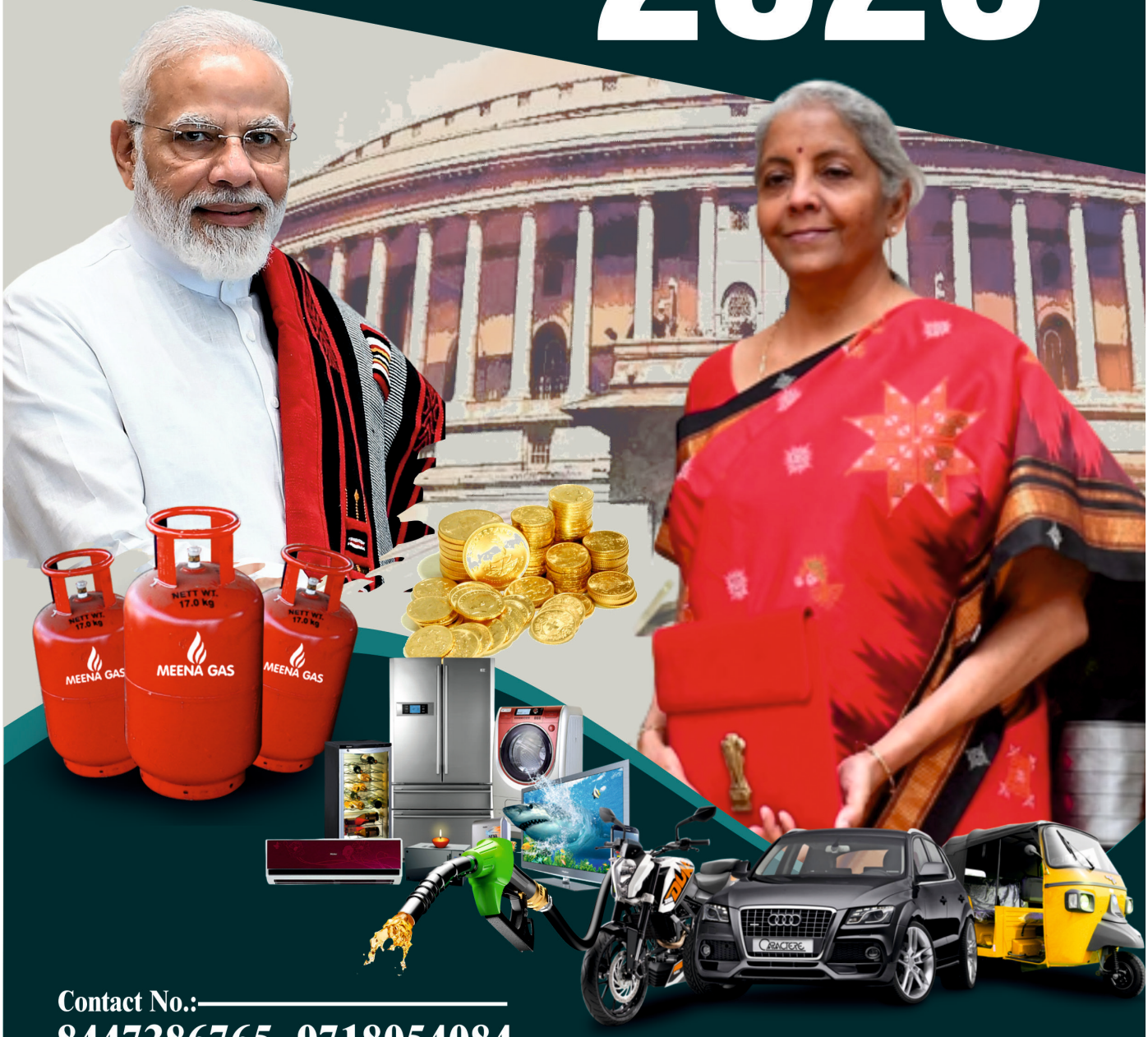

Contact No.:
8447386765, 9718054084

U-135, Ground & 2nd Floor, Vikas Marg. Baba Complex,
Near Laxmi Nagar Metro Station Gate No.:- 3 Shakarpur, Delhi - 92

बजट और सर्वेक्षण - 2023

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या

Contents

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 1-14

आर्थिक सर्वेक्षण 2023

परिदृश्यः 2023-24

केंद्रीय बजट 2023-24: समग्र विश्लेषण 15-35

केंद्रीय बजट 2023-24: समग्र विश्लेषण

बजट की सात प्राथमिकताओं 'सप्तेऋषि' में शामिल है

प्राथमिकता- 1: समावेशी विकास:

प्राथमिकता- 2: अंतिम छोर तक पहुँचना

प्राथमिकता- 3: अवसंरचना और निवेश

प्राथमिकता 4: क्षमता को उजागर करना

प्राथमिकता- 5: हरित विकास:

प्राथमिकता- 6: युवा शक्ति:

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्र

1 आर्थिक सर्वेक्षण 2023

आर्थिक सर्वेक्षण 2023

2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8 प्रतिशत रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। विकास अनुमान का आशावादी पक्ष विभिन्न सकारात्मक तथ्यों पर आधारित है, जैसे निजी खपत में मजबूती जिसमें उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया है; पूंजीगत व्यय की उच्च दर (कैपेक्स); सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज, जिसने संपर्क आधारित सेवाओं– रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंगमॉल, सिनेमा आदि- के लिए लोगों को सक्षम किया है; शहरों के निर्माण स्थलों पर प्रवासी श्रमिकों के लौटने से भवन निर्माण सामग्री के जमा होने में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है, कॉरपोरेट जगत के लेखा विवरण पत्रों में मजबूती; पूंजी युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो ऋण देने में वृद्धि के लिए तैयार हैं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण में बढ़ोतरी।

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में 'आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23' पेश किया, जिसका अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5 प्रतिशत रहेगी। इस अनुमान की बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी और घरेलू तौर पर आरबीआई द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना की जा सकती है।

सर्वेक्षण कहता है कि वित्त वर्ष 2024 में विकास की गति तेज रहेगी क्योंकि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के लेखा विवरण पत्रों के मजबूत होने से ऋण अदायगी और पूंजीगत निवेश के शुरू होने का अनुमान है। आर्थिक विकास को लोक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार तथा ऐतिहासिक उपायों जैसे पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से समर्थन मिलेगा, जो निर्माण उत्पादन को बढ़ावा देंगे।

सर्वेक्षण कहता है कि वास्तविक स्तर पर मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 8.7 प्रतिशत रही थी।

कोविड-19 के तीन लहरों तथा रूस-यूक्रेन संघर्ष के बावजूद एवं फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों द्वारा महंगाई दर में कमी लाने की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती दर्ज की गई है और आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ा है। दुनियाभर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी

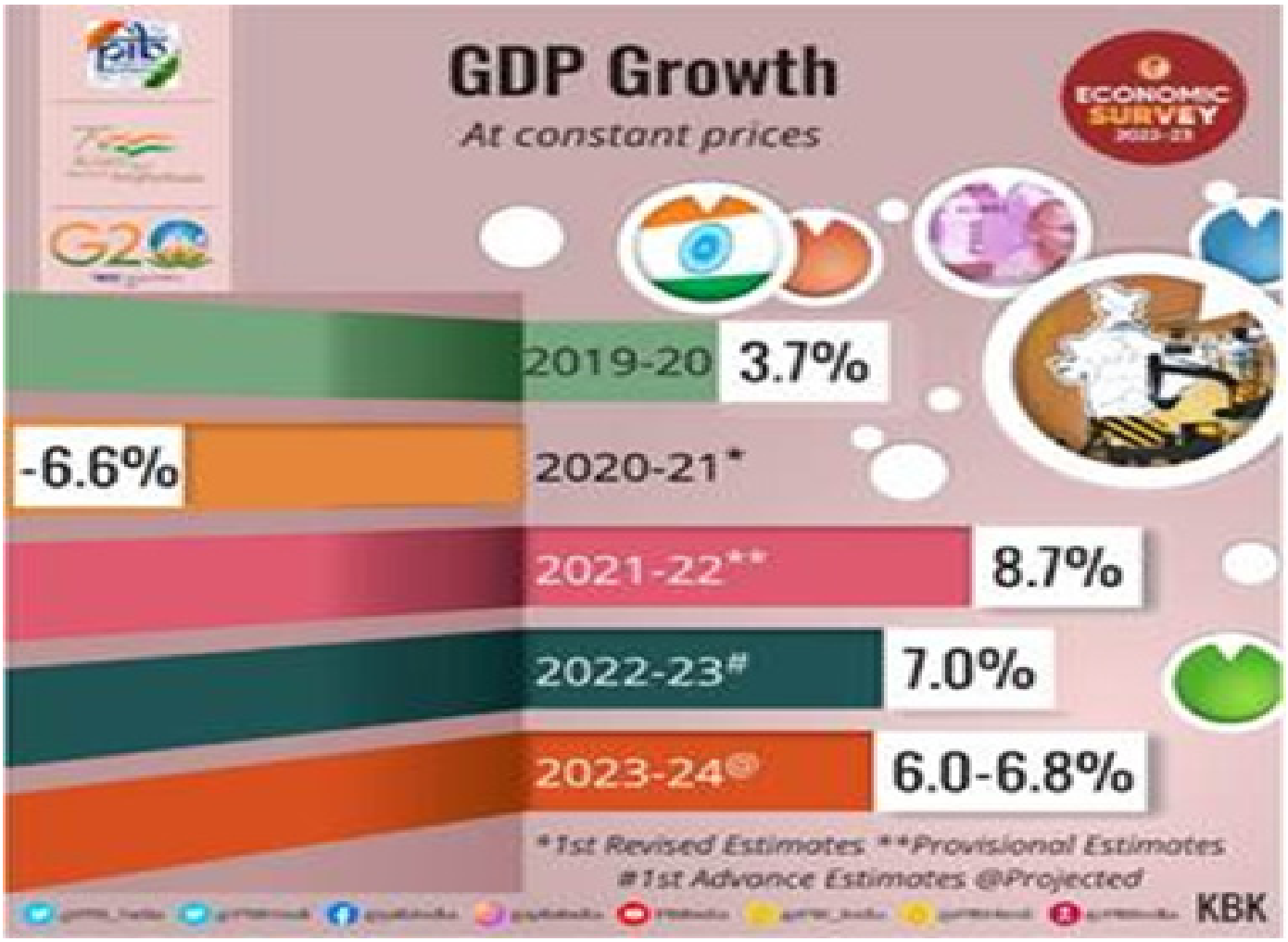

अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.5 – 7.0 प्रतिशत रहेगी।

सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है, जिसने रोजगार के सृजन में मदद की है। यह शहरी बेरोजगारी दर में कमी तथा कर्मचारी भविष्य निधि के कुल पंजीकरण में तेजी के माध्यम से दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त, विश्व के दूसरे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, जिसमें 2 बिलियन खुराकें दी गई हैं, ने भी उपभोक्ताओं के मनोभाव को मजबूती दी है, जिससे खपत में वृद्धि होगी। निजी पूंजीगत निवेश का नेतृत्व करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के अवसरों का तेजी से सृजन हो सके।

भारत के विकास दृष्टिकोण को निम्न से बढ़ावा मिला है– (i) चीन के कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान लहर से पूरी दुनिया के प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रही हैं। (ii) चीन की अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना न तो महत्वपूर्ण है और न ही निरंतर है। (iii) विकसित अर्थव्यवस्थाओं में (ई) मंदी के रुझानों से मौद्रिक मजबूती में कमी आई है; भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत से कम रही है, जिससे देश में पूंजीगत प्रवाह बढ़ा है तथा (iv) उद्योग जगत का रुझान बेहतर हुआ है, जिससे निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि हुई है।

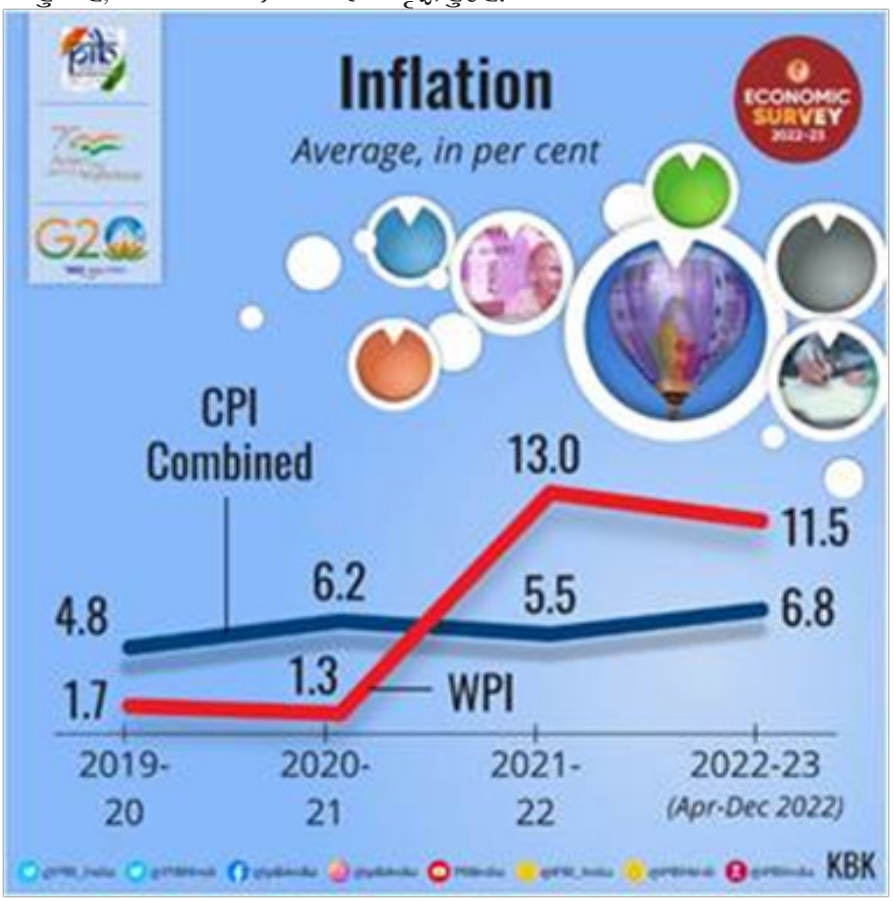

सर्वेक्षण कहता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी-नवम्बर, 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.6 प्रतिशत रही और इसे केन्द्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का समर्थन मिला। एमएसएमई क्षेत्र में रिकवरी की गति तेज हुई है, जो उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की धनराशि से परिलक्षित होती है। उनकी आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ऋण संबंधी चिंताओं को दूर कर रही है। इसके अलावा बैंक ऋण में हुई वृद्धि, उधार लेने वालों के बदलते रुझानों से भी प्रभावित हुई है, जो जोखिम भरे बॉन्ड मार्किट में निवेश कर रहे हैं, जहां धन अर्जन अधिक होता है। यदि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कम होती है और ऋण की वास्तविक लागत नहीं बढ़ती है तो वित्त वर्ष 2024 के लिए ऋण वृद्धि तेज रहेगी।

केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वित्त वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में 63.4 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख घटक रहा है। 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही से निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। वर्तमान रुझानों के अनुसार लगता है कि पूरे वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय बजट हासिल कर लिया जाएगा। निजी पूंजीगत निवेश में भी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत के लेखा विवरण पत्र मजबूत हुए हैं जिससे ऋण देने में वृद्धि होगी।

सर्वेक्षण ने महामारी के कारण निर्माण गतिविधियों में आई बाधाओं को रेखांकित किया है। सर्वेक्षण कहता है कि टीकाकरण से प्रवासी श्रमिकों को शहरों में वापस आने में सुविधा मिली है। इससे आवास बाजार मजबूत हुआ है। यह इस बात से परिलक्षित होता है कि विनिर्माण सामग्री के भंडार में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है, जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीने रह गया है।

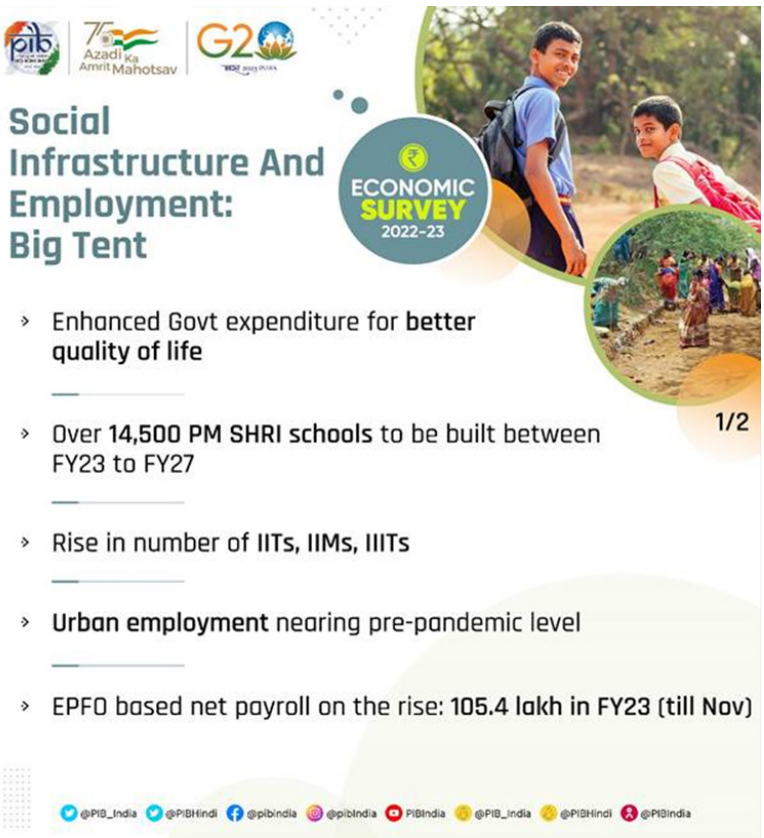

सर्वेक्षण कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान कर रही है और अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों में बदलाव लाने में मदद कर रही है। पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और इनके प्रभावों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने भी अनुशंसा प्रदान की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के परिणामों ने भी दिखाया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक ग्रामीण कल्याण संकेतक बेहतर हुए हैं, जिनमें लिंग, प्रजनन दर, परिवार की सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

सर्वेक्षण उम्मीद करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभावों से मुक्त हो चुकी है और वित्त वर्ष 2022 में दूसरे देशों

की अपेक्षा तेजी से पहले की स्थिति में आ चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब वित्त वर्ष 2023 में महामारी-पूर्व के विकास मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि चालू वर्ष में भारत ने यूरोपीय संघर्ष के कारण हुई मुद्रास्फीति में वृद्धि को कम करने की चुनौती का सामना किया है। सरकार और आरबीआई के द्वारा किए गए उपायों और वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में आई कमी से नवंबर, 2022 से खुदरा मुद्रास्फीति को आरबीआई की लक्ष्य-सीमा से नीचे लाने में मदद मिली।

हालांकि, यह इस बारे में सतर्क करता है कि रुपया, जो कि अधिकांश मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, में मूल्यह्रास की चुनौती यूएस फेड द्वारा नीतिगत दरों में और वृद्धि किए जाने की संभावना के साथ बनी हुई है। सीएडी का बढ़ना भी जारी रह सकता है क्योंकि वैश्विक जिंस की कीमतों में उच्चता बनी हुई है और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति भी मजबूत बनी हुई है। निर्यात प्रोत्साहन का नुकसान आगे भी संभव है क्योंकि धीमी पड़ती वैश्विक वृद्धि और व्यापार चालू वर्ष की दूसरी छमाही में वैश्विक बाजार के आकार को कम करता है।

इस प्रकार से वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है और इसके बाद के वर्षों में भी आमतौर पर कमजोर रहने की संभावना है। धीमी मांग की वजह से वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी आएगी और वित्त वर्ष 2024 में भारत के सीएडी में सुधार होगा। हालांकि चालू खाता शेष के लिए नकारात्मक जोखिम मुख्य रूप से घरेलू मांग और कुछ हद तक निर्यात द्वारा संचालित तेज रिकवरी से उत्पन्न होता है। सीएडी पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है क्योंकि चालू वर्ष की विकास गति अगले वर्ष की विकास गति बनाए रखेगी।

सर्वेक्षण में इस महत्वपूर्ण तथ्य की भी जानकारी दी गई है कि सामान्य तौर पर, पिछले समय में वैश्विक आर्थिक झटके काफी गंभीर रहे हैं लेकिन समय के बीतने के साथ इनसे बाहर निकला गया है परन्तु इसने शताब्दी के तीसरे दशक में परिवर्तन किया क्योंकि 2020 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कम से कम तीन झटके झेलने पड़े हैं।

यह सब महामारी से प्रभावित वैश्विक उत्पादन में आई कमी से प्रारंभ हुआ जिसे रूस-यूक्रेन संघर्ष ने विश्व को मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर कर दिया फिर फेडरल रिजर्व के पीछे-पीछे अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए समकालिक नीतिगत दरों में वृद्धि की। यूएस फेड द्वारा दरों में की गई वृद्धि ने अमेरिकी बाजारों में पूंजी को आकर्षित किया, जिससे अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी

डॉलर का मूल्य बढ़ गया। परिणामस्वरूप चालू घाटा सीएडी बढ़ गया और निवल आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि आई। दर में वृद्धि और सतत मुद्रास्फीति ने आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक के अक्टूबर 2022 के अपडेट में 2022 और 2023 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया। चीनी अर्थव्यवस्था की क्षीणता ने आगे विकास के पूर्वानुमानों को और कमजोर किया। मौद्रिक तंगी के अलावा धीमी वैश्विक वृद्धि भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न वित्तीय संक्रमण का कारण बन सकती हैं जहां गैर-वित्तीय क्षेत्र का ऋण वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे अधिक बढ़ गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बने रहने और केन्द्रीय बैंकों द्वारा दरों में अधिक वृद्धि के संकेत से, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ा हुआ दिखाई देता है।

भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती, सीएडी का बढ़ना, और निर्यात की स्थिर वृद्धि अनिवार्य रूप से यूरोप में भू-राजनीतिक विवाद का परिणाम है। जैसा कि इन गतिविधियों ने वित्त वर्ष 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है, दुनिया भर में कई एजेंसियां रूक-रूक कर भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने विकास पूर्वानुमान को नीचे की ओर संशोधित कर रही हैं। एनएसओ द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों सहित ये पूर्वानुमान अब मोटे तौर पर 6.5-7.0 प्रतिशत की सीमा में हैं।

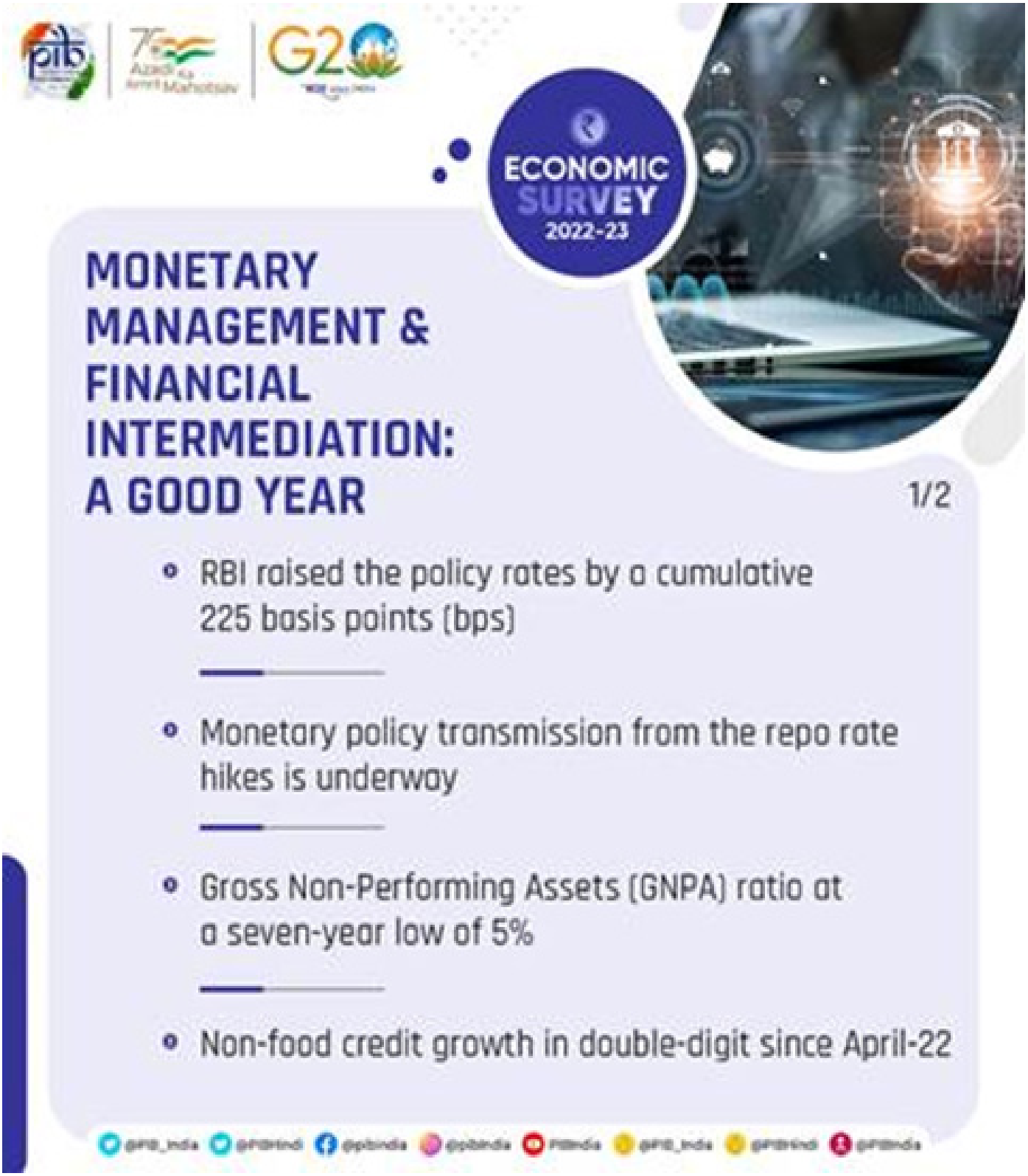

नीचे की ओर दर्शाने के बावजूद, वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास का अनुमान लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक बना हुआ है और यहां तक की महामारी से पहले के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि से थोड़ा अधिक है।

आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 में तेजी से बढ़ती शीर्ष दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मजबूत वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और कड़ी घरेलू मौद्रिक नीति के बावजूद, यदि भारत अभी भी 6.5 और 7.0 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद करता है और वह भी आधार प्रभाव के लाभ के बिना, तो यह भारत के अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन का प्रतिबिंब है, और अर्थव्यवस्था के विकास कारकों को पुनः प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और फिर से सक्रिय करने की इसकी क्षमता है। भारत के आर्थिक लचीलेपन को विकास के लिए घरेलू प्रोत्साहन में देखा जा सकता है जो बाहरी प्रोत्साहनों की जगह ले सकता है। निर्यात में वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में कम हो सकती है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022 में उनके उछाल और वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही ने उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ाने में हल्की तेजी से क्रूज मोड में बदलाव के लिए प्रेरित किया है।

इसके परिणामस्वरूप, विनिर्माण और निवेश गतिविधियों को मजबूती मिली। जब निर्यात-वृद्धि में कमी आई, तब घरेलू खपत में आयी तेजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आगे ले जाने में मदद की। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी खपत वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 58.4 प्रतिशत रही, जो 2013-14 के बाद से सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसे व्यापार, होटल और परिवहन जैसी संपर्क-गहन सेवाओं का समर्थन मिला, जिनमें पिछली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक आधार पर 16 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई।

हालांकि कई अर्थव्यवस्थाओं की घरेलू खपत में सुधार हुआ, लेकिन भारत में यह सुधार पैमाने की दृष्टि से प्रभावशाली था। इसने घरेलू क्षमता उपयोग की वृद्धि में योगदान दिया। नवंबर 2022 में घरेलू निजी खपत में तेजी जारी रही। इसके अलावा, आरबीआई के दिसंबर 2022 में जारी उपभोक्ता विश्वास के ताजा सर्वेक्षण ने वर्तमान और संभावित रोजगार तथा आय के संबंध में सुधार की ओर इशारा किया।

सर्वेक्षण एक और सुधार की ओर भी इशारा करता है और कहता है कि "नियंत्रित मांग को खोलना" आवास बाजार में भी परिलक्षित हुआ क्योंकि आवास ऋण की मांग में तेजी आई। परिणामस्वरूप, आवास सूची में गिरावट आई है, कीमतें मजबूत हो रही हैं, और नए आवासों का निर्माण गति पकड़ रहा है और इसने असंख्य बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को प्रोत्साहित किया है जिसे आगे बढ़ाने के लिए निर्माण क्षेत्र जाना जाता है। आवास बाजार को उठाने में टीकाकरण कवरेज के सार्वभौमिकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके अभाव में, प्रवासी श्रमशक्ति नए आवासों का निर्माण करने के लिए वापस नहीं आ सकती थी।

आवास के अलावा, निर्माण गतिविधि, सामान्य रूप से वित्त वर्ष 2023 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है क्योंकि केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बढ़ाए गए पूंजीगत बजट (कैपेक्स) का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

देश के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय गुणक के अनुसार, देश का आर्थिक उत्पादन पूंजीगत व्यय की मात्रा से कम से कम चार गुना बढ़ेगा। राज्य भी अपनी पूंजीगत व्यय योजनाओं के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरह, राज्यों के पास भी पूंजीगत कार्यों के लिए केंद्र की अनुदान सहायता और 50 वर्षों में चुकाने योग्य ब्याज मुक्त ऋण द्वारा समर्थित एक बड़ा पूंजी बजट है।

इसके अलावा, भारत सरकार के पिछले दो बजटों में पूंजीगत व्यय पर जोर देना कोई ऐसी पहल नहीं थी, जिसका उद्देश्य केवल देश के अवसंरचना-निर्माण की कमी को दूर करना था। यह एक रणनीतिक पैकेज का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य गैर-रणनीतिक पीएसई और सार्वजनिक क्षेत्र की निष्क्रिय संपत्तियों का विनिवेश करके आर्थिक परिदृश्य में निवेश आकर्षित करना था।

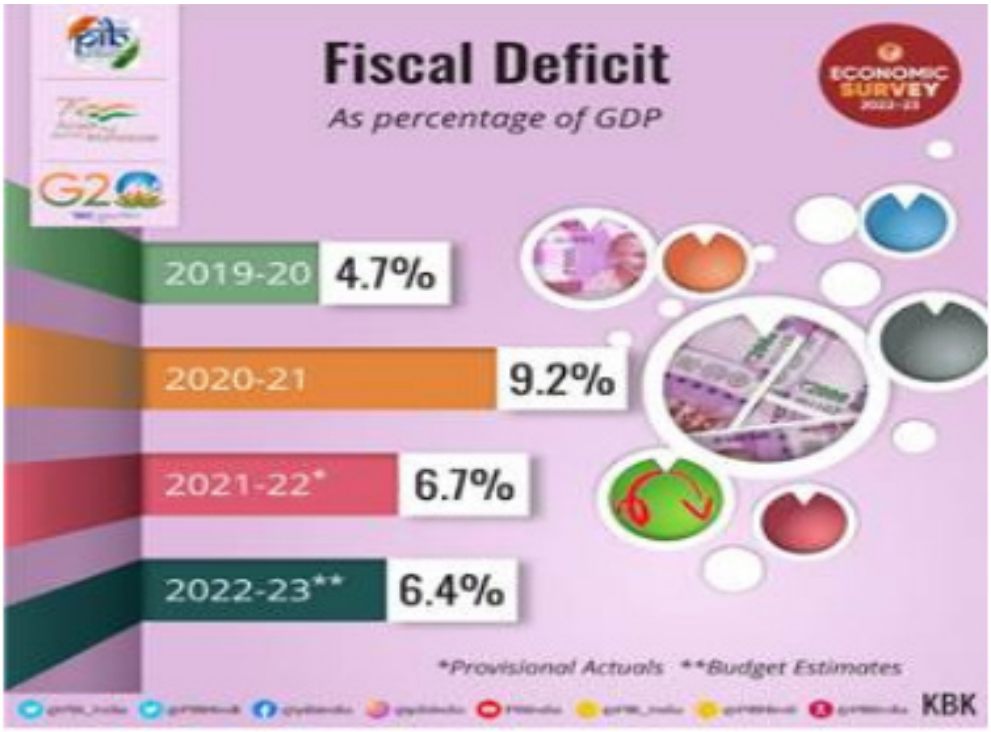

यहां, तीन तथ्य इसका समर्थन करते हैं, सबसे पहले वित्त वर्ष 2023 के पूंजीगत बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि, साथ ही इसके खर्च की उच्च दर, दूसरा प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह और जीएसटी संग्रह में वृद्धि, जो बजटीय राजकोषीय घाटे के भीतर पूंजीगत बजट के पूर्ण खर्च को सुनिश्चित करता है। राजस्व व्यय में वृद्धि ने भी पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है और तीसरा, 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही के बाद से निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि। साक्ष्य, निजी कंपनियों द्वारा घोषित परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय में तेजी के रुझान को दर्शाते हैं।

निर्यात मांग में वृद्धि, खपत में तेजी और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने कॉरपोरेट्स के निवेश/विनिर्माण गतिविधियों के सुधार में योगदान दिया है, उनके मजबूत लेखा विवरण पत्रों ने भी उनकी व्यय योजनाओं को साकार करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के गैर-वित्तीय ऋण आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक के दौरान, भारतीय गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र ऋण और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ऋण में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में, लगभग तीस प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

भारत का बैंकिंग क्षेत्र भी ऋण की मांग को पूरा करने के लिए आगे आया है, क्योंकि 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही के बाद से वर्ष-दर-वर्ष ऋण की वृद्धि दोहरे अंकों की रही है और अधिकांश क्षेत्रों में यह वृद्धि जारी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्त में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, नियमित अंतराल पर लाभ अर्जित किये जा रहे हैं और उनकी गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा त्वरित रूप से समाधान/परिसमापन किया जा रहा है। साथ ही, सरकार पीएसबी को अच्छी तरह से पूंजीयुक्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि उनका पूंजी जोखिम-भारित समायोजित अनुपात (सीआरएआर) पर्याप्तता के प्रारंभिक स्तर से ऊपर रहने को सुनिश्चित किया जा सके। बहरहाल, वित्तीय ताकत ने बैंकों को कम ऋण वित्तपोषण को पूरा करने में मदद की है, जिसे वित्त वर्ष 23 में अब तक कॉर्पोरेट बॉन्ड और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) द्वारा समर्थन मिला है। कॉरपोरेट बॉन्ड पर बढ़ती प्राप्तियां और ईसीबी पर उच्च ब्याज/हेजिंग लागत ने इन लेखा पत्रों को पिछले वर्ष की तुलना में कम आकर्षक बना दिया है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति की दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो इसकी लक्ष्य सीमा से बाहर है। साथ ही, यह इतना भी अधिक नहीं है, जो निजी खपत को रोक दे और इतना भी कम नहीं है कि निवेश करने के उत्साह को कमजोर कर दे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकोनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियां

भारत पर महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में एक महत्वपूर्ण जीडीपी संकुचन देखा गया। अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था जनवरी 2022 की ओमिक्रॉन लहर के बावजूद पटरी पर आने लगी थी। इस तीसरी लहर ने भारत में आर्थिक गतिविधियों को उतना प्रभावित नहीं किया, जितना महामारी की पिछली लहरों ने जनवरी 2020 में इसका प्रकोप शुरू होने पर प्रभावित किया था। हालांकि, यूरोप में संघर्ष ने वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति की प्रत्याशा में एक संशोधन आवश्यक कर दिया। जनवरी 2022 में देश की खुदरा मद्रास्फीति आरबीआई की स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली गई थी। यह नवंबर से 6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर से नीचे लौटने से पहले दस महीनों के लिए लक्ष्य सीमा से ऊपर रही।

इसमें कहा गया है कि वैश्विक वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन संघर्ष-पूर्व के स्तरों की तुलना में अभी भी अधिक हैं और उन्होंने सीएडी को और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही भारत की गति से बढ़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में भारत के पास सीएडी को वित्तपोषित करने और भारतीये रुपये में अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है।

परिदृश्य: 2023-24

2023-24 के लिए अनुमान के विवरण में समीक्षा में बताया गया है कि महामारी से भारत की भरपाई अपेक्षाकृत तीव्र थी और ठोस घरेलू मांग के समर्थन व पूंजीगत निवेश में वृद्धि से आगामी वर्षों में प्रगति होगी। इसमें बताया गया है कि सशक्त वित्तीय घटकों के बल पर निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण प्रक्रिया का अंतर्निहित लक्षण परिलक्षित है और पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्र की सावधानी के लिए भरपाई करना और सरकार द्वारा पर्याप्त पूंजीगत व्यय जुटाना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2023 तक पिछले 7 वर्षों में बजटीय पूंजीगत व्यय में 2.7 गुणा वृद्धि हुई, जिससे पूंजीगत व्यय को मजबूती मिली। वस्तु एवं सेवाकर की शुरुआत और दिवाला एवं दीवालियापन संहिता जैसे रचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ी और वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2022 के अनुसार, वैश्विक विकास के वर्ष 2022 में 3.2 प्रतिशत से धीमा होकर वर्ष 2023 में 2.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक उत्पादन में धीमी वृद्धि के साथ बढ़ती अनिश्चितता व्यापार वृद्धि को कम कर देगी।

वैश्विक व्यापार में वृद्धि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्ष 2022 में 3.5 प्रतिशत से 2023 में 1.0 प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान किया गया है।

बाह्य दृष्टि से, चालू खाता शेष के जोखिम अनेक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जबकि वस्तुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से कम हो गई हैं, वे अभी भी संघर्ष-पूर्व के स्तर से ऊपर हैं। वस्तुओं की उच्च कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग से भारत के कुल आयात बिल में वृद्धि होगी और चालू खाता शेष में अलाभकारी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात वृद्धि को स्थिर करके इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। यदि चालू खाते के घाटे में और वृद्धि होती है तो मुद्रा पर मूल्यह्रास का दबाव बढ़ेगा।

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति सख्ती की प्रक्रिया को लंबा कर सकती है और इसलिए, उधार लेने की लागत "लंबे समय तक अधिक" रह सकती है। ऐसे परिदृश्य में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2024 में कम वृद्धि हो सकती है। तथापि धीमे वैश्विक विकास के परिदृश्य से दो उम्मीदें पैदा होती हैं- तेल की कीमतें कम रहेंगी, और भारत का सीएडी वर्तमान के स्तर से बेहतर होगा। कुल मिलाकर बाह्य स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

भारत का समावेशी विकास

सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकास तब समावेशी होता है, जब यह रोजगार सृजित करता है। आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि चालू वित्त वर्ष में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 9.8 प्रतिशत से घटकर एक वर्ष बाद (सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में) 7.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी सुधार हुआ है। यह वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के महामारी से प्रेरित मंदी से उभरने की पुष्टि करता है।

वित्त वर्ष 2021 में, सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को

वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही। सिबिल की एक हालिया रिपोर्ट (ईसीएलजीएस अंतर्दृष्टि, अगस्त 2022 ने दिखाया कि इस योजना ने एमएसएमई को कोविड झटके का सामना करने में मदद की है, जिसमें 83 प्रतिशत उधारकर्ताओं ने ईसीएलजीएस का सूक्ष्म-उद्यमों के रूप में लाभ उठाया है। इन सूक्ष्म इकाइयों में, आधे से अधिक का समग्र जोखिम 10 लाख रुपये से कम था।

इसके अलावा, सिबिल डेटा से भी यह पता चलता है कि ईसीएलजीएस उधारकर्ताओं की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति दरें उन उद्यमों की तुलना में कम थीं जो ईसीएलजीएस के लिए पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021 में गिरावट के बाद एमएसएमई द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी तब से बढ़ रहा है और अब वित्तीय वर्ष 2020 के पूर्व-महामारी स्तर को पार कर गया है, जो छोटे व्यवसायियों की वित्तीय सशक्त और एमएसएमई के लिए लक्षित सरकार के उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सरकार द्वारा लागू की गई योजना किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में "व्यक्तिगत भूमि पर काम" के संबंध में तेजी से अधिक संपत्ति का सृजन कर रही है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आबादी के आधे हिस्से को कवर करने वाले परिवारों के लिए लाभकारी पीएम-किसान जैसी योजनाएं और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जुलाई 2022 की यूएनडीपी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाल ही में मुद्रास्फीति के प्रकरण में अच्छे लक्षित समर्थन के कारण गरीबी पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार को दर्शाता है, जिसमें लिंग, प्रजनन दर, घरेलू सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं को कवर किया गया है।

अब तक भारत ने अपने आर्थिक लचीलेपन में देश के विश्वास को मजबूत किया है। अर्थव्यवस्था ने इस प्रक्रिया में विकास की गति को खोए बिना रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण हुए बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई निकासी से प्रभावित हुए बगैर चालू वर्ष 2022 में भारत के शेयर बाजारों में सकारात्मक वापसी हुई। कई उन्नत देशों और क्षेत्रों की तुलना में भारत की मुद्रास्फीति दर अपनी लक्षित सीमा से बहुत अधिक नहीं बढ़ी।

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने बड़े एक राष्ट्र की अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उसे 'पुनः प्राप्त' किया है, जो खो गया था, उसे 'नवीनीकृत' किया है, जो रुका हुआ था और उसे 'पुनः सक्रिय' किया है, जो वैश्विक महामारी के दौरान और यूरोप में संघर्ष के बाद से धीमा हो गया था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है

सर्वेक्षण में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 6 चुनौतियों का सामना कर रही है। कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के कारण रुकावट आई, रूस-यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला, मुख्य रूप से खाद्य, ईंधन तथा उर्वरक की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई और महंगाई को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि के कारण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर में उछाल आया और सकल आयात अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता घाटा बढ़ा। वैश्विक गतिरोध की संभावनाओं का सामना करते हुए, राष्ट्रों ने अपनी संबंधित आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए मजबूरी महसूस की, सीमापार व्यापार धीमा कर दिया, जिसने विकास के लिए चौथी चुनौती पेश की। शुरुआत से पांचवीं चुनौती बढ़ रही थी, क्योंकि चीन ने अपनी नीतियों से प्रेरित काफी मंदी का अनुभव किया। विकास के लिए छठी मध्यम अवधि की चुनौती महामारी के आने के डर से शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों के नुकसान के रूप में देखी गयी।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, भारत ने भी इन असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने उनका बेहतर तरीके से सामना किया।

पिछले ग्यारह महीनों में, विश्व अर्थव्यवस्था ने लगभग उतने ही व्यवधानों का सामना किया है, जितना दो वर्षों में महामारी के कारण हुआ है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इसने मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ाया, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार शुरू हो गया था, जो 2020 में उत्पादन संकुचन को सीमित करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और अति-समायोजन कार्य मौद्रिक नीतियों से समर्थित था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति, जो अधिकांश वैश्विक राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक सहजता के लिए जिम्मेदार है, ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को पार कर लिया है। बढ़ती कमोडिटी की कीमतों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में भी उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया, जो अन्यथा 2020 में आउटपुट संकुचन को संबोधित करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा अंशांकित राजकोषीय प्रोत्साहन के आधार पर निम्न मुद्रास्फीति क्षेत्र में थे।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप दुनियाभर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। पूंजी के पलायन ने बाद में अन्य मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया-जनवरी और सितंबर 2022 के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 16.1 प्रतिशत मजबूत हुआ। अन्य मुद्राओं को परिणामी मूल्यह्रास सीएडी को बढ़ा रहा है और शुद्ध आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ा रहा है।

2 बजट 2022-23

केंद्रीय बजट 2023-24: समग्र विश्लेषण

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्री य बजट 2023-24 पेश किया। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संवृद्धि के पथ पर है और तमाम चुनौतियों के बावजूद यह नए भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है।
- वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं।
- उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
- 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार।
- 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज।
- पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण।

'केंद्रीय बजट' और उसके संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ध्यातव्य है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:

- राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
- व्यय अनुमान।
- पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण।
- आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।

संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:

1. बजट की प्रस्तुति।
2. आम चर्चा।
3. विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
4. अनुदान मांगों पर मतदान।
5. विनियोग विधेयक पारित करना।
6. वित्त विधेयक पारित करना।

केंद्रीय बजट 2023-24 भाषण की मुख्य विशेषताएं:

- कई संकटों के बीच सहज: आर्थिक विकास का अनुमान 7% है, जो कि COVID-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- G20 प्रेसीडेंसी: 'वसुधैव कुटुम्बकम' की थीम के साथ, भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सतत आर्थिक विकास की सुविधा के लिए एक महत्वाकांक्षी, जन-केंद्रित एजेंडा चला रहा है।

2014 से अब तक की उपलब्धियां- समावेशिता:

केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं:

अमृत काल का विजन- एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था:

- 'अमृत काल' शब्द वैदिक ज्योतिष से आया है और एक प्रकार के सुनहरे युग का संकेत देता है।
- भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा। अमृत काल का विज़न एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित है। यह दर्शाता है कि भारत में आने वाला समय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के साथ सबसे समृद्ध होने वाला है।
- 'अमृत काल' बेहतर भविष्य की आशा का भी वर्णन करता है, जहां भारत आत्मनिर्भर होगा और अपने सभी मानवीय दायित्वों को पूरा करेगा।

- **भविष्य की संभावनाएं:** यह बजट पिछले बजट में रखी गई नींव और भारत@100 के लिए तैयार की गयी नींव पर बनने की उम्मीद करता है, जो एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करता है।
- बजट में इंडिया@100 तक पहुँचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है:
  - स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
  - पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM विकास)
  - मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा
  - हरित विकास

सप्तर्षि: बजट 2023-24 की प्राथमिकताएँ: बजट में निम्नलिखित सात प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। वे एक-दूसरे के पूरक हैं और अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले 'सप्तर्षि' के रूप में कार्य करते हैं।

बजट की सात प्राथमिकताओं 'सप्तऋषि' में शामिल है –

1. समावेशी विकास।
2. अंतिम छोर-अंतिम व्यपक्ति तक पहुंच।
3. बुनियादी ढांचा और निवेश।
4. निहित क्षमताओं का विस्तायर।
5. हरित विकास।
6. युवा शक्ति।
7. वित्तीकय क्षेत्र।

प्राथमिकता- 1: समावेशी विकास:

कृषि: केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य गरीबों और मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के अलावा किसानों का समावेशी और व्यापक विकास करना है। बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा, जबकि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार बजट में कृषि को तकनीक से जोड़कर कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है ताकि दीर्घकाल में किसानों को व्यापक लाभ मिल सके।

केंद्रीय बजट 2023 कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन

कृषि शिक्षा और अनुसंधान समेत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार करीब सवा लाख करोड़ रुपये है। विभिन्न सरकारी पहलों और योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में आवंटन निम्नलिखित है-

- **पीएम किसान:** इसमें से रुपये का प्रावधान। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** देश में करीब 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए काफी फायदा हुआ है। इस बार इसके लिए 23 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **डिजिटल कृषि मिशन:** डिजिटल कृषि मिशन के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित परिणाम होंगे:
  - समावेशी किसान-केंद्रित समाधान
  - फसल योजना/स्वास्थ्य के लिये प्रासंगिक सूचना सेवाएँ
  - कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुँच
  - कृषि-प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्ट-अप्स का विकास-समर्थन

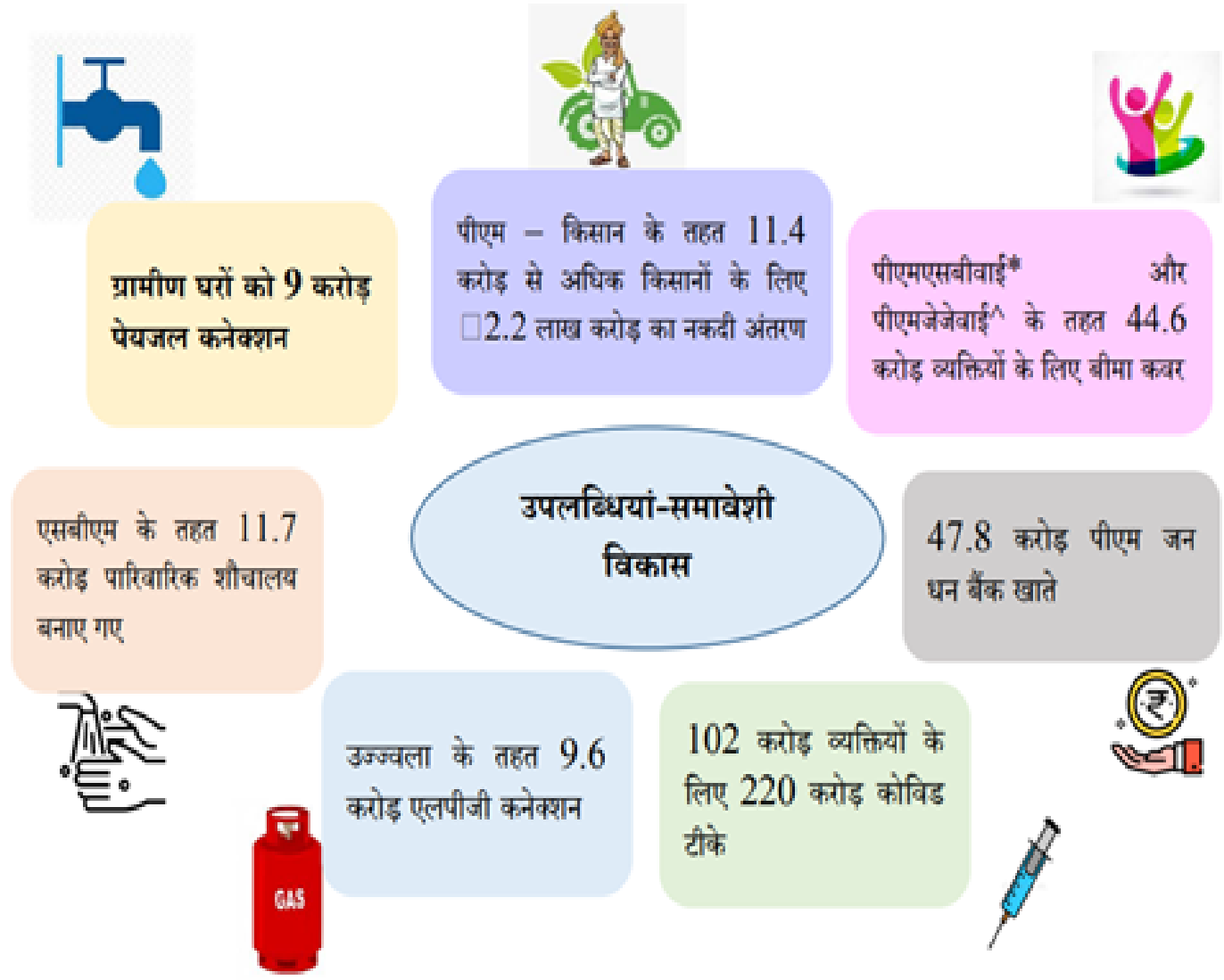

- **प्राकृतिक खेती:** प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 3 साल में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे।

- **कृषि सहकारी समितियाँ:** "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये सरकार अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने और कवर न किये गए गाँवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना बना रही है।
- **कृषक उत्पादक संगठन (FPO):** FPO के माध्यम से छोटे और मध्यम किसानों को संगठित करते हुए उन्हें कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 10 हजार नए FPO का गठन किया जा रहा है। यह FPO छोटे और मध्यम किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका लाभ इन किसानों को मिलने लगा है। भविष्य में इसी गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष नए FPO के गठन के लिए 955 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए लाभकारी कृषि इंफ्रा फंड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** यह केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिए बजट बढ़ाकर 1,623 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 5 वर्षों की अवधि में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **कृषि-ऋण:** पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
- **बाजरे को श्री-अन्न के नाम से जाना जाएगा:** भारत को 'श्री अन्न' (पोषक अनाज/कदन्न) हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिये 'भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को साझा करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
- **बागवानी विकास:** बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्चर गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धाता बढ़ाने के उद्देश्यस से किया जाएगा।

शिक्षा और कौशल:

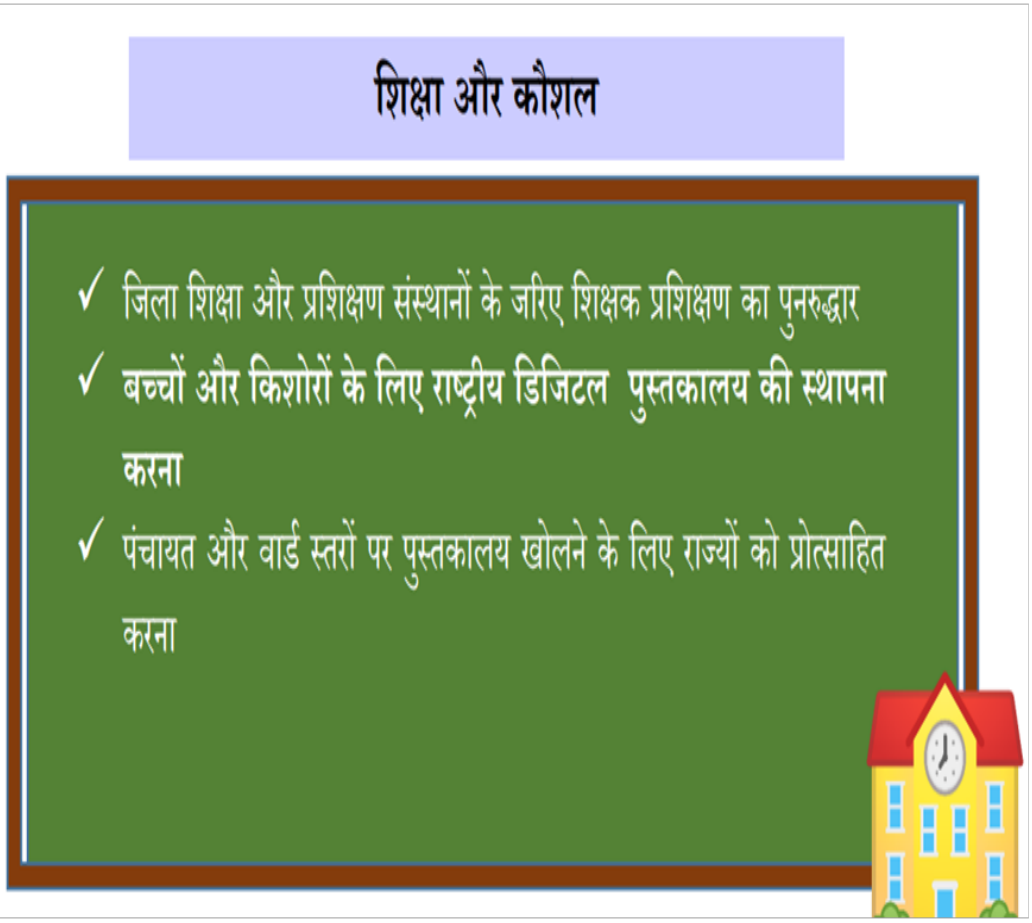

- केंद्रीय बजट 2023 में शिक्षा के लिए आवंटित राशि अब तक की सबसे अधिक राशि है और 2022-2023 के लिए अनुमानित राशि से लगभग 8.2% अधिक है।
- केंद्र सरकार शिक्षक शिक्षा को नया स्वरूप देगी, जिला स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी, और बच्चों और युवाओं को विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली किताबें प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगी, ताकि उन्हें कोविड-19 महामारी द्वारा सीखने के नुकसान से उबरने में मदद मिल सके।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा बजट 2023-24 के हिस्से के रूप में फार्मेसी और स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्र के सामान्य विकास के लक्ष्य के साथ अनुसंधान उद्देश्यों के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की।

स्वास्थ्य:

अपने 2023-24 के केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार का कुल बजट मोटे तौर पर 86,175 करोड़ रुपये (10 बिलियन डॉलर) होगा - यानी प्रत्येक नागरिक के लिए लगभग 615 रुपये। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि है और मुद्रास्फीति की दर से कम है। सही मायनों में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य खर्च में गिरावट आई है।

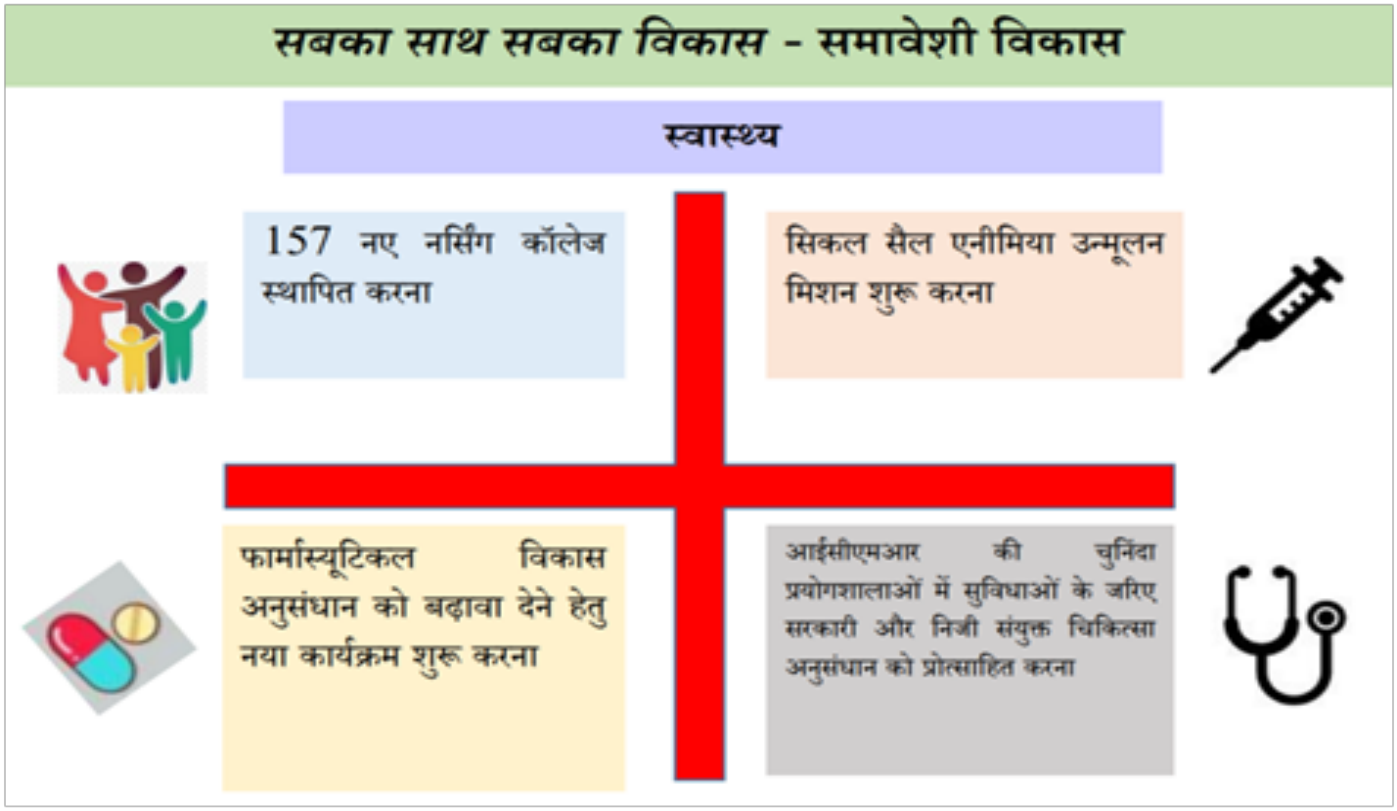

आवंटन

- वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्साह महाविद्यालयों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा:
  - जागरूकता बढ़ाना
  - प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों (0-40 वर्ष की आयु) की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग
  - केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श

प्राथमिकता- 2: अंतिम छोर तक पहुँचना

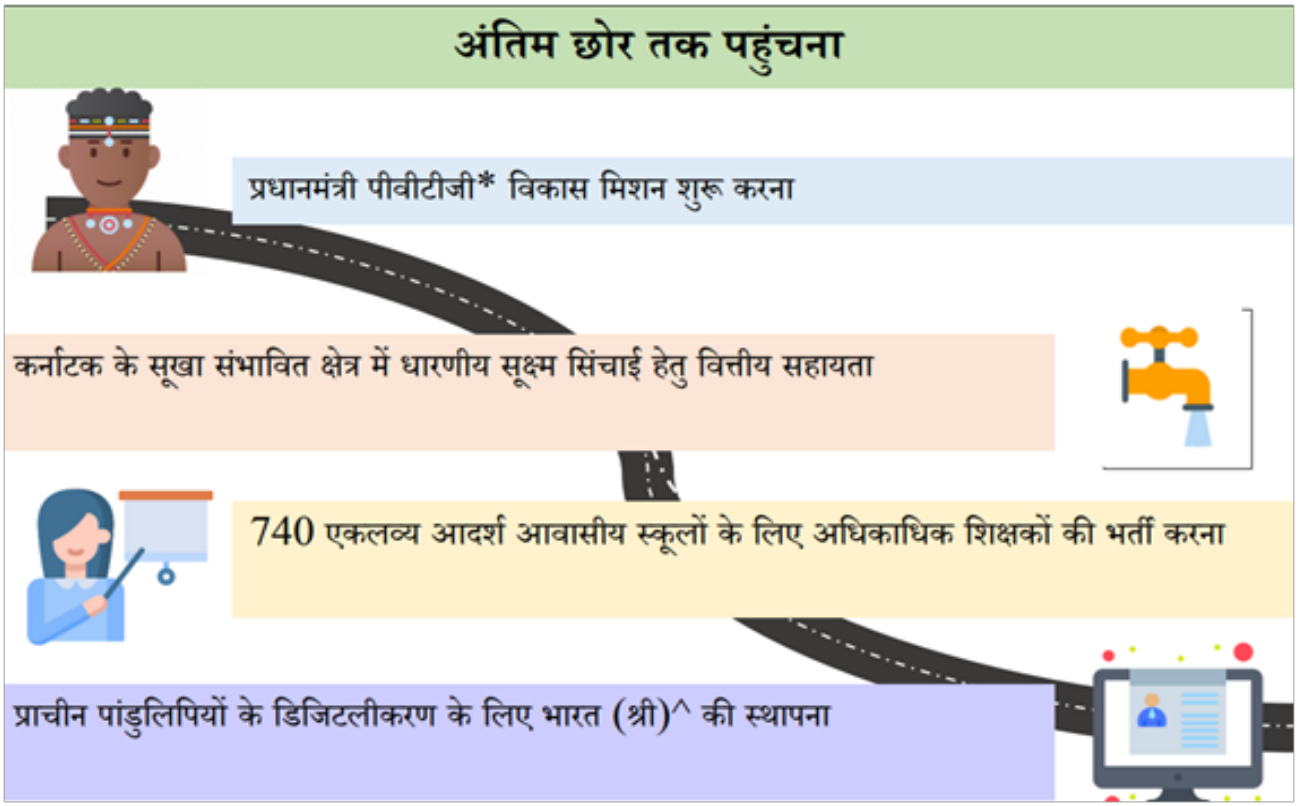

'अंतिम छोर तक पहुंचने' के उद्देश्य पर अधिक ध्यान देने के लिए, सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है।

फोकस क्षेत्र	उपायों की घोषणा की
आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम	• स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, और बुनियादी ढांचे जैसे कई डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करने वाले एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम को लॉन्च किया।
प्रधान मंत्री PVTG विकास मिशन	• विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। • यह PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा। • अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	• अगले तीन वर्षों में, केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए पानी	• कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में, स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
पीएम आवास योजना	• पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।
भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन (भारत श्री)	• 'भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन' डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में स्थापित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
गरीब कैदियों के लिए सहायता	• ऐसे गरीब व्यक्तियों के लिए जो जेलों में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता- 3: अवसंरचना और निवेश

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर व्यापक गुणक प्रभाव पड़ता है। बजट निवेश और रोजगार सृजन के चक्र को गति देने की दिशा में आगे बढ़ा है।

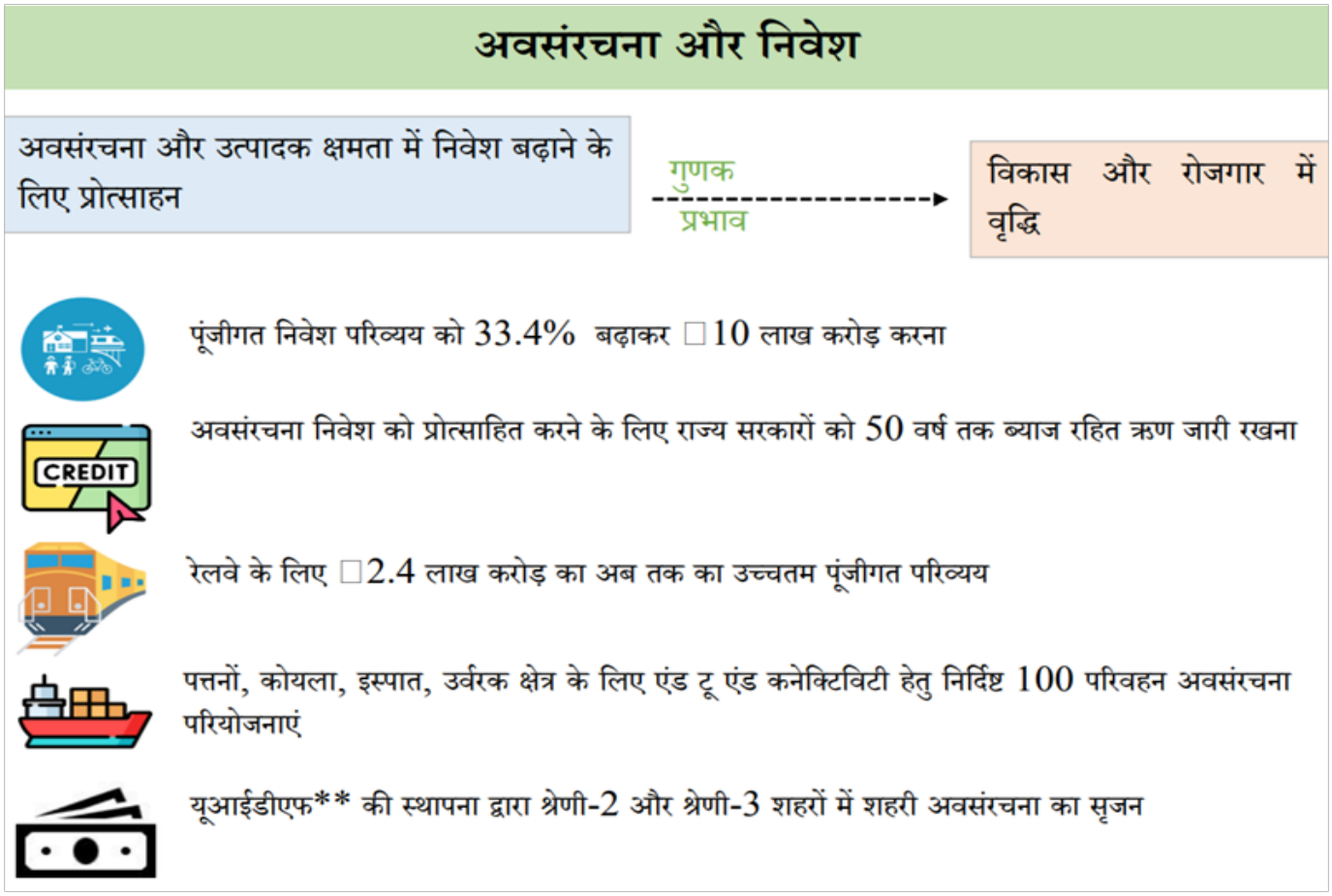

फोकस क्षेत्र	उपायों की घोषणा की
विकास और नौकरियों के चालक के रूप में पूंजी निवेश	• पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। • विकास क्षमता और रोजगार सृजन, निजी निवेश में भीड़ बढ़ाने और वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ एक गद्दी प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।
प्रभावी पूंजीगत व्यय	• केंद्र के 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% होगा।
पूंजी निवेश के लिए राज्य सरकारों को सहायता	• बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और पूरक नीतिगत कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखना।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश के अवसरों में वृद्धि	• इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय रेलवे, सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली सहित बुनियादी ढांचे में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची	• अमृत काल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची की समीक्षा की जाएगी।
रेलवे	• रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है।
लॉजिस्टिक्स	• बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। उन्हें निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता पर लिया जाएगा।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी	• क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एयरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।
कल के सतत शहर	• राज्यों और शहरों को शहरों को 'भविष्य के टिकाऊ शहरों' में बदलने के लिए शहरी नियोजन सुधार और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका अर्थ है भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त संसाधन, पारगमन-उन्मुख विकास, शहरी भूमि की उपलब्धता और सामर्थ्य में वृद्धि, और सभी के लिए अवसर।
शहरों को म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए तैयार करना	• प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिंग-फेंसिंग यूजर चार्जेज के जरिए शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
शहरी अवसंरचना विकास निधि	• एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) की स्थापना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में कमी के माध्यम से की जाएगी। यह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। • राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि यूआईडीएफ तक पहुंच बनाते समय उपयुक्त उपयोगकर्ता शुल्कों को अपनाया जा सके। सरकार को इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
शहरी स्वच्छता	• मैनहोल से मशीन-होल मोड में संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई के लिए सक्षम बनाया जाएगा। सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्राथमिकता 4: क्षमता को उजागर करना

सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करके सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

फोकस क्षेत्र	उपायों की घोषणा की
मिशन कर्मयोगी	• केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। • सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके कौशल को उन्नत करने और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, iGOT कर्मयोगी लॉन्च किया है। • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है। • भरोसे पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। • यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र	• "मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया" के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • कृषि, स्वास्थ्य और स्थायी शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत के प्रमुख खिलाड़ी अंतःविषय अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और स्केलेबल समस्या समाधान विकसित करने में भागीदार होंगे।
नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी	• एक नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। यह अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगा।
अपने ग्राहक को जानिए (KYC) प्रक्रिया का सरलीकरण	• KYC प्रक्रिया को 'एक आकार सभी फिट बैठता है' के बजाय 'जोखिम-आधारित' दृष्टिकोण अपनाते हुए सरल बनाया जाएगा। • डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को भी एक केवाईसी प्रणाली के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पहचान और पते को अपडेट करने के लिए एक स्थान पर समाधान	• विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुरक्षित व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतन के लिए एक स्थान पर समाधान स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग किया जाएगा।
सामान्य व्यापार पहचानकर्ता	• स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया	• विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक ही सूचना को अलग-अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। • एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत रूपों में सूचना या रिटर्न की ऐसी फाइलिंग, फाइलर की पसंद के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी।
विवाद से विश्वास I - MSMEs के लिए राहत	• कोविड अवधि के दौरान MSMEs द्वारा अनुबंधों को निष्पादित करने में विफल रहने के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95% सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।
विवाद से विश्वास II - संविदात्मक विवादों का निपटारा	• सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए, जहां मध्यस्थता निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा रही है, मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक समाधान योजना शुरू की जाएगी। • यह विवाद के लंबित स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा।
राज्य सहायता मिशन	• नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन तीन साल तक जारी रहेगा।
परिणाम आधारित वित्त पोषण	• प्रतिस्पर्धात्मक विकास आवश्यकताओं के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने के लिए, चुनिंदा योजनाओं के वित्तपोषण को पायलट आधार पर 'इनपुट-आधारित' से 'परिणाम-आधारित' में बदला जाएगा।
ई-न्यायालय	• न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 को 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा।
फिनटेक सेवाएं	• अधिक फिनटेक नवीन सेवाओं को सक्षम करने के लिए, व्यक्तियों के लिए डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे का विस्तार किया जाएगा।
एंटिटी डिजिलॉकर	• एक एंटिटी डिजिलॉकर एमएसएमई, बड़े कारोबारियों और चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ, जब भी आवश्यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए होगा।

5जी सेवाएं	• 5जी सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला का एहसास हो सके। • प्रयोगशालाओं में अन्य के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों जैसे अनुप्रयोग शामिल होंगे।
प्रयोगशाला में विकसित हीरे (LGD)	• LGD बीजों और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, IIT में से किसी एक को पाँच वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। • उत्पादन की लागत को कम करने के लिए LGD बीजों पर सीमा शुल्क दर की समीक्षा के प्रस्ताव का संकेत दिया जाएगा।

प्राथमिकता- 5: हरित विकास:

वित्त मंत्री ने कहा, "हम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हरित विकास के लिए कई कार्यक्रम लागू कर रहे हैं... वे कार्बन तीव्रता को कम करने और हरित रोजगार सृजित करने में मदद करेंगे।"

माननीय प्रधान मंत्री ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए "लाइफ" या पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए एक दृष्टिकोण दिया है। भारत हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए 2070 तक 'पंचामृत' और शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर हमारे फोकस पर आधारित है।

फोकस क्षेत्र	उपायों की घोषणा की
हरित हाइड्रोजन मिशन	• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा, और देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व ग्रहण करने में मदद करेगा। • सरकार 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य बना रही है।

ऊर्जा संक्रमण	• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों, और ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स	• 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग से सपोर्ट किया जाएगा। • पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी।
नवीकरणीय ऊर्जा निकासी	• लद्दाख से 13 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली का निर्माण 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा।
हरित ऋण कार्यक्रम	• एक हरित ऋण कार्यक्रम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। • यह कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा, और ऐसी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करेगा।
PM-PRANAM	• वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
GOBARdhan योजना	• सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट स्थापित किए जाएंगे। • इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्र और 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल हैं। • आने वाले समय में, प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% सीबीजी अधिदेश पेश किया जाएगा। • बायोमास के संग्रह और जैव खाद के वितरण के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र	• अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। • इसके लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार करेंगे।
MISHTI	• 'मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम', MISHTI, को मनरेगा, कैम्पा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से, जहां भी संभव हो, समुद्र तट के किनारे और सॉल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए शुरू किया जाएगा।
अमृत धरोहर	• सरकार अमृत धरोहर के माध्यम से उनके संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी, एक योजना जो अगले तीन वर्षों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जाएगी, और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ावा देगी।
तटीय नौवहन	• तटीय नौवहन व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के साथ पीपीपी मोड के माध्यम से यात्रियों और माल दोनों के लिए ऊर्जा कुशल और परिवहन के कम लागत वाले साधन के रूप में तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
वाहन प्रतिस्थापन	• केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित। • पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी।

प्राथमिकता- 6: युवा शक्ति:

हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और 'अमृत पीठ' को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, कौशल पर ध्यान केंद्रित किया है, ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करती हैं, और व्यापार के अवसरों का समर्थन किया है।

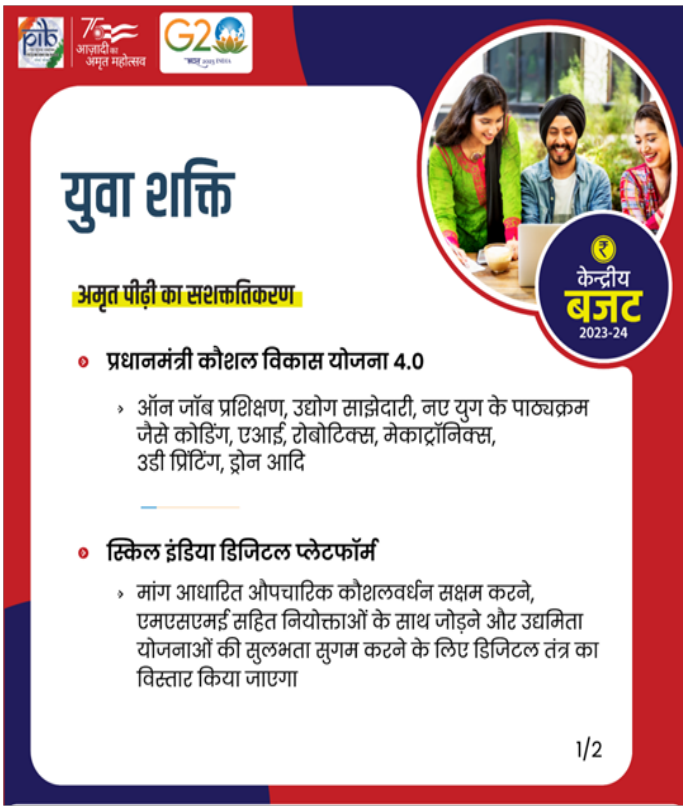

फोकस क्षेत्र	उपायों की घोषणा की
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0	• अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। • ऑन-जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर बल दिया जाएगा। • यह योजना उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी। • युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म	• स्किलिंग के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ और विस्तारित किया जाएगा ताकि मांग-आधारित औपचारिक स्किलिंग को सक्षम बनाया जा सके, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ा जा सके और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना	• तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
पर्यटन	• चैलेंज मोड के माध्यम से कम से कम 50 गंतव्यों का चयन किया जाएगा। फिजिकल कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट्स के लिए उच्च मानक और पर्यटकों की सुरक्षा जैसे पहलुओं के अलावा, पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। • प्रत्येक गंतव्य को एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन के विकास का फोकस देशी--विदेशी पर्यटकों पर रहेगा। • 'देखो अपना देश' पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के कौशल और उद्यमिता विकास का तालमेल बिठाया जाएगा। • थीम आधारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन योजना' भी शुरू की गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को भी सुगम बनाया जाएगा।
यूनिटी मॉल	• राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए और अन्य राज्यों में ऐसे उत्पादों के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए अपनी राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्र

वित्त मंत्री ने कहा, "वित्तीय क्षेत्र में हमारे सुधारों और प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन, बेहतर और तेज सेवा वितरण, ऋण तक पहुंच में आसानी और वित्तीय बाजारों में भागीदारी हुई है।"

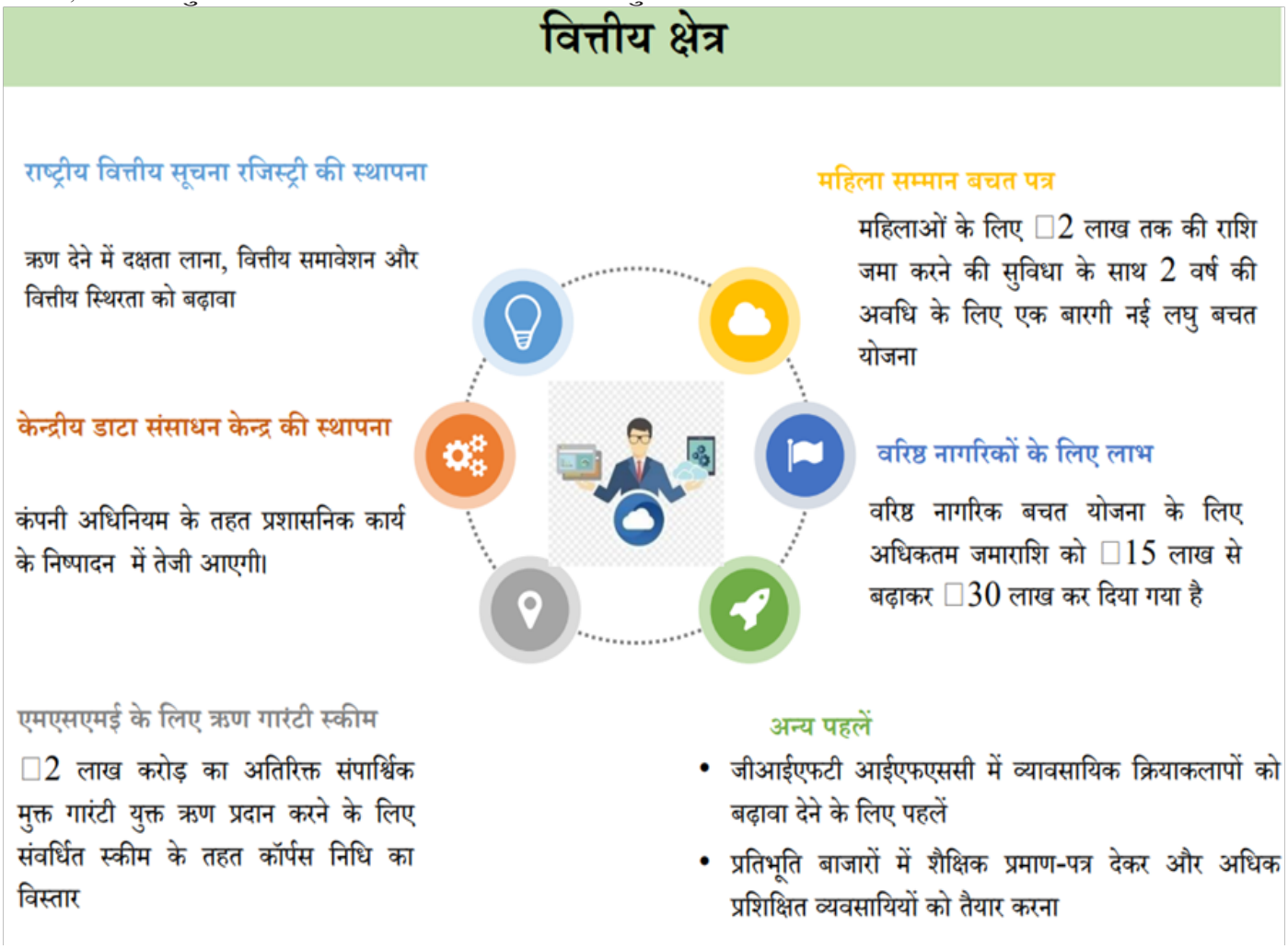

फोकस क्षेत्र	उपायों की घोषणा की
MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी	• संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। • यह 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण को सक्षम करेगा। • ऋण की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री	• वित्तीय और सहायक जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। • एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, और इसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
वित्तीय क्षेत्र के विनियम	• वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन की सुविधा के लिए, आवश्यक और व्यवहार्य सार्वजनिक परामर्श को विनियमन बनाने और सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में लाया जाएगा। • अनुपालन की लागत को सरल, आसान और कम करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए वे सार्वजनिक और विनियमित संस्थाओं के सुझावों पर विचार करेंगे। • विभिन्न विनियमों के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी।

GIFT IFSC	• GIFT IFSC में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे: • दोहरे विनियमन से बचने के लिए SEZ अधिनियम के तहत IFSCA को शक्तियां सौंपना, • IFSCA, SEZ प्राधिकरणों, GSTN, RBI, SEBI और IRDAI से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना, • विदेशी बैंकों की IFSC बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना, • व्यापार के लिए एक्जिम बैंक की सहायक कंपनी की स्थापना • पुनर्वित्त, मध्यस्थता, सहायक सेवाओं के लिए वैधानिक प्रावधानों के लिए IFSCA अधिनियम में संशोधन, और SEZ अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचना, और अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों को वैध अनुबंधों के रूप में मान्यता देना।
डेटा दूतावास	• डिजिटल निरंतरता समाधान की तलाश करने वाले देशों के लिए, सरकार GIFT IFSC में अपने डेटा दूतावासों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी।
बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और निवेशक संरक्षण में सुधार	• बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।
प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण	• प्रतिभूति बाजार में पदाधिकारियों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए, सेबी को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने, विनियमित करने, बनाए रखने और लागू करने और डिग्री, डिप्लोमा के पुरस्कार को मान्यता देने के लिए सशक्त किया जाएगा। और प्रमाण पत्र।
सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर	• कंपनी अधिनियम के तहत फील्ड कार्यालयों के साथ फाइल किए गए विभिन्न फॉर्मों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनियों को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
शेयरों और लाभांशों की पुनः प्राप्ति	• निवेशकों के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण से दावा न किए गए शेयरों और भुगतान न किए गए लाभांशों को आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए, एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
डिजिटल भुगतान	• डिजिटल भुगतानों को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। 2022 में, वे लेनदेन में 76% और मूल्य में 91% की वृद्धि दिखाते हैं। इस डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता 2023-24 में जारी रहेगी।
आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र	• एक बार की नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के लिए।

राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति:

- **पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग:** वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिये अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिये। इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा, हालाँकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा सशर्त होगा, जैसे:
  - पुराने सरकारी वाहनों को बदलना।
  - शहरी नियोजन में सुधार।
  - शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिका बॉण्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना।
  - पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण।
  - एकीकृत मॉल का निर्माण।
  - बच्चों और किशोरों हेतु पुस्तकालयों तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
  - केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना।
- **राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति:** राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.5% घाटा रखने की अनुमति है, इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिये निर्धारित है।

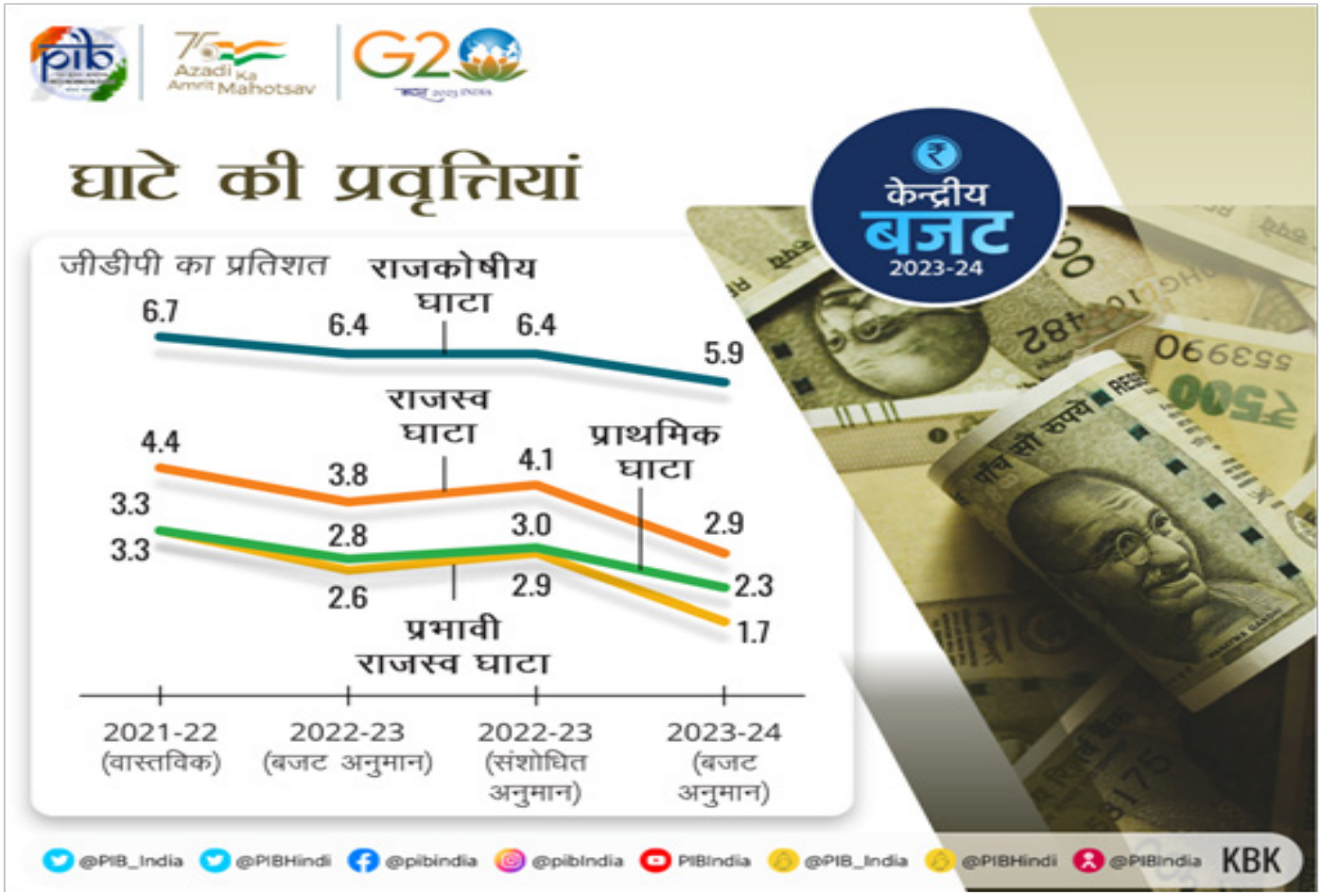

संशोधित अनुमान 2022-23:

- कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर): 24.3 लाख करोड़ रुपए।
  - शुद्ध कर प्राप्ति: 20.9 लाख करोड़ रुपए।
- कुल व्यय: 41.9 लाख करोड़ रुपए।
  - पूंजीगत व्यय: 7.3 लाख करोड़ रुपए।
- राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%।

बजट अनुमान 2023-24:

- बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियाँ 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिये दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाज़ार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सकल बाज़ार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिये इस योजना पर अडिग रहने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार:

व्यक्तिगत आयकर: व्यक्तिगत आयकर से संबंधित पाँच प्रमुख घोषणाएँ हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढाँचे में स्लैब की संख्या को घटाकर पाँच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

अन्य कर सुधार:

मानक कटौती: नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन के लिये कटौती को 15,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

MSMEs: सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिये प्रकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है, जब तक कि नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5% से अधिक न हो। MSME को किये गए भुगतान के लिये कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर प्राप्ति (Timely Receipt) में सहयोग करने के लिये किया गया हो।

सहकारिता: 31 मार्च, 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है। सहकारी समितियों की नकद निकासी पर स्रोत पर की गई टैक्स (कर) कटौती को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

स्टार्टअप: स्टार्टअप्स को आयकर लाभ प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिये हानियों को अग्रेषित करने की अवधि को निगमन के 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग: ऑनलाइन गेमिंग पर करदेयता को TDS के साथ और निकासी के समय अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में जीती गई कुल राशि पर करदेयता के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

सोना: सोने के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट में परिवर्तन और इसके विपरीत (Vice Versa) को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।

आयकर से छूट: आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग जिसकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आवास, शहर, कस्बे और गाँव के विकास लिये नियामक एवं विकास गतिविधियों या कार्यों हेतु की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव है। अग्निवीर निधि को EEE स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किये गए भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। अग्निवीरों की कुल आय में की गई कटौती राशि को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो कि उन्होंने योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने उनकी सेवा के लिये उनके खाते में हस्तांतरित किया है।

कॉमन IT रिटर्न फॉर्म: करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिये सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करने की योजना के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म के लिये एक प्रस्ताव पेश किया।

वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें:

कर की दर	वर्तमान आय स्लैब	प्रस्तावित आय स्लैब
1. शून्य	2.5 लाख रूपए तक	3 लाख रूपए तक

2. 5%	2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक	3 लाख से 6 लाख रूपए तक
3. 10%	5 लाख से 7.5 लाख रूपए तक	6 लाख से 9 लाख रूपए तक
4. 15%	7.5 लाख से 10 लाख रूपए तक	9 लाख से 12 लाख रूपए तक
5. 20%	10 लाख से 12 लाख रूपए तक	12 लाख से 15 लाख रूपए तक
6. 25%	12 लाख से 15 लाख रूपए तक	-
7. 30%	15 लाख रूपए से अधिक	15 लाख रूपए से अधिक

अप्रत्यक्ष कराधान हेतु प्रस्तावित सुधार:

- **सीमा शुल्क:** वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। निर्दिष्ट सिगरेट्स पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty- NCCD) में लगभग 16% की वृद्धि की गई है।
- **शुल्क में वृद्धि:**
  - सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुएँ
  - चाँदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क
- **शुल्क से छूट:**
  - मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित संपीड़ित बायोगैस।
  - परीक्षण एजेंसियाँ जो परीक्षण और/या प्रमाणन उद्देश्यों हेतु वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण/घटकों, उप-प्रणालियों तथा टायरों का आयात करती हैं।
  - साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिये निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समयसीमा

को बढ़ाकर 31.03.2024 कर दिया गया है।

- रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त विकृत एथिल अल्कोहल।

सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन:

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित किया जा रहा है ताकि आवेदन दायर होने के बाद समाधान हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिये नौ महीने की समयसीमा निर्धारित की जा सके।
- एंटी डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) और सेफगार्ड उपायों के उद्देश्य एवं दायरे को स्पष्ट करने के लिये सीमा शुल्क अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
- **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में भी किये जाएँगे बदलाव:**
  - GST के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी।
  - कर के लिये चक्रवृद्धि राशि को कर राशि के 50-150% से घटाकर 25-100% कर दिया जाएगा।
  - कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।
  - रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की अवधि नियत तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित होगी।
  - अपंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECO) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।

रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है?

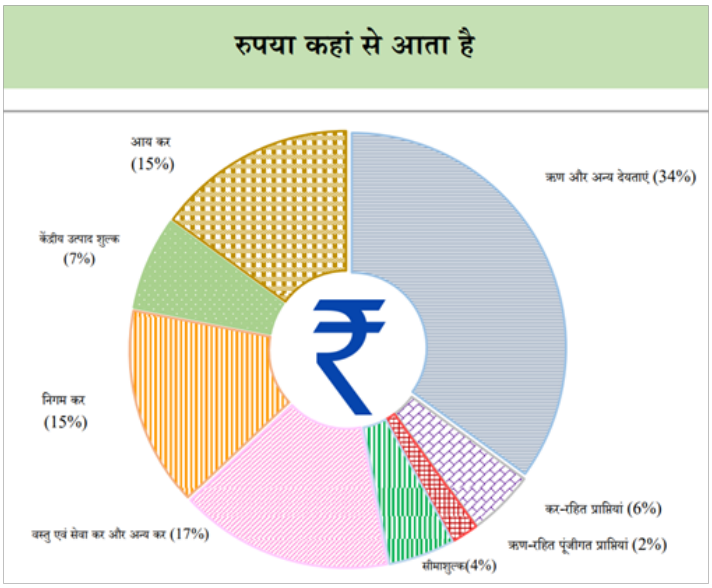

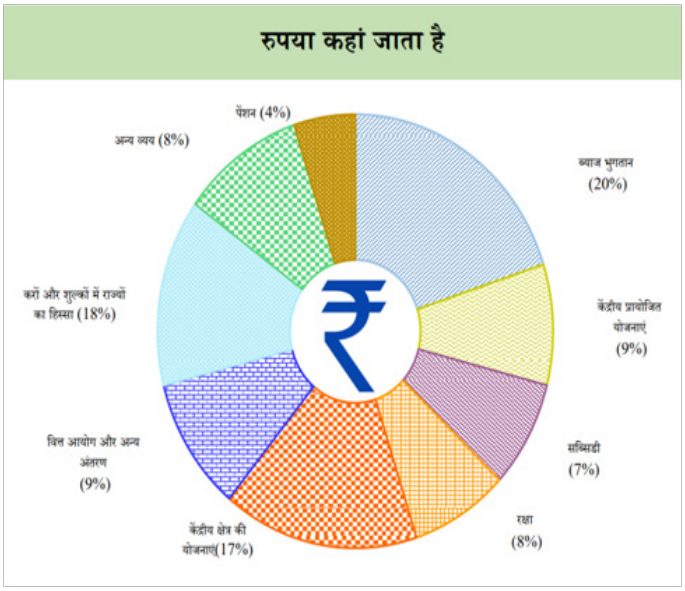

आलेख जानकारी (इन्फोग्राफिक्स):

व्यक्तिगत आयकर: नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है, जिसका अर्थ है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले चपरासी को कोई कर नहीं देना होगा। नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढांचे में स्लैब की संख्या को घटाकर पांच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर -3 लाख कर दिया गया है।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव: इसने कम कर दरों के साथ कर संरचना के सरलीकरण पर जोर दिया ताकि अनुपालन बोझ को कम करने और कर प्रशासन में सुधार करने में मदद मिल सके। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।

कर रियायतों का बेहतर लक्ष्यीकरण: कर रियायतों और छूटों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए आवासीय घरों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपये तय की गई है।

MSME से संबंधित प्रस्ताव: सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिये प्रकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है, जब तक कि नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5% से अधिक न हो। MSME को किये गए भुगतान के लिये कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर प्राप्ति (Timely Receipt) में सहयोग करने

के लिये किया गया हो।

सहकारिता: 31 मार्च, 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है। सहकारी समितियों की नकद निकासी पर स्रोत पर की गई टैक्स (कर) कटौती को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।।

स्टार्ट-अप्स: बजट में स्टार्ट-अप्स के लिए आयकर लाभों के लिए निगमन की तिथि को 31.03.2023 से बढ़ाकर 31.03.2024 करने का प्रस्ताव है।

CGST अधिनियम में संशोधन: GST के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। कर के लिये चक्रवृद्धि राशि को कर राशि के 50-150% से घटाकर 25-100% कर दिया जाएगा। कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की अवधि नियत तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित होगी। अपंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECO) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।।

कर परिवर्तनों के निहितार्थ: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लगभग -38,000 करोड़ का राजस्व छोड़ दिया जाएगा, जबकि लगभग -3,000 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा।